<u>विद्यार्थी कल्याण न्यास द्वारा 24 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन के अवसर पर माननीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के अभिभाषण का मसौदा</u>

1. विद्यार्थी कल्याण न्यास द्वारा आयोजित किए जा रहे उत्साह और उमंग से भरपूर इस राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन में उपस्थित महानुभावों, विशेष रूप से कृषि छात्रों जिनके कंधों पर देश में कृषि के भावी विकास की जिम्मेदारी होगी, के बीच मुझे यहां आकर प्रसन्नता हो रही है। हमारे देश में वर्तमान और भावी कृषि के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय **"एग्रीविजन 2018"** का चयन करने के लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूं।,

2. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूनाइटिड नेशन्स पापुलेशन फण्ड - यूएनएफपीए) की विश्व की जनसंख्या की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 35.6 करोड़ युवा हैं जो 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच के हैं और भारत में यह युवा शक्ति विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। आशा है कि वर्ष 2020 तक चीन की 77.6 करोड़ कार्यशील आबादी के बाद भारत में कार्यशील आबादी बढ़कर 59.2 करोड़ हो जाएगी। इसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि युवाओं का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। शीघ्र ही भारत विश्व में सबसे युवा देश बन जाएगा । इस कारण से भी भारत के युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर हैं, वे अपने डिजिटल ज्ञान से, नई नई प्रौद्योगिकियों का न केवल स्वयं लाभ उठायें वरन् बढ़ती उम्र के हमारे किसान भाइयों को जिन्हें टैक्नोलॉजी की थोड़ी कम जानकारी है, को भी उनकी जानकारी दें जिससे जहां एक ओर युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे वहीं कृषि और किसानी की बेहतरी भी होगी।

3. हमारे देश में कृषि का विकास अधिकांशत: हमारे कृषि शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है। भारत में काफी अधिक संख्या में वैज्ञानिक कर्मियों के साथ शिक्षा और अनुसंधान प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी कृषि शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों में से एक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (National Agricultural Research and Education System) के अंतर्गत देशभर में हमारे 100 से अधिक अनुसंधान संस्थान, 75 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 690 कृषि विज्ञान केन्द्र (अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा 25 कृषि विज्ञान केन्द्रों का शिलान्यास किया गया है) हैं जो बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि में समन्वयन करने, मार्ग निर्देशन करने तथा अनुसंधान एवं शिक्षा प्रबंधन में कार्यरत हैं ।

4. खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी के युग से निकल कर खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से आत्म-निर्भरता के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में भारत में कृषि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से एक लंबा रास्ता तय किया है। लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन और लगभग 300 मिलियन टन से अधिक बागवानी उत्पादन हासिल करना इसका एक उदाहरण है। एक मजबूत और आत्म-निर्भर

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के बोध से कृषि अनुसंधान और विकास को समेकित करते हुए ठोस राष्ट्रीय प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप कृषि का पूरा परिदृश्य बदल गया जिसे "हरित क्रांति" कहा गया। इस सफलता से राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रणालियों में किसानों और नीति निर्धारकों का विश्वास बढ़ा और अन्य क्रान्तियों जैसे कि 'श्वेत क्रान्ति', 'नीली क्रान्ति', 'पिंक क्रान्ति', 'सिल्वर क्रान्ति', 'Sweet क्रान्ति' एवं 'पीत क्रान्ति' आदि की शुरूआत हुई।

5. आने वाले वर्षों में कुपोषण और अप्रत्यक्ष भूख की चिन्ताओं का समाधान किया जाना है। इस प्रयास में गैर अनाज वाली खाद्य मदों को शामिल करके फूड-बास्केट में विविधता लाने के लिए अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके फलस्वरूप फलों, सब्जियों, दूध, मास, अंडा और मछली की उत्पादकता, उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि होना आरंभ हो गया जिसके परिणामस्वरूप भोजन पौषणिक रूप से अधिक सन्तुलित हो गया परन्तु इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

6. भविष्य में कृषि क्षेत्र भारत की आर्थिक सुरक्षा का केन्द्र बना रहेगा। भारत में एक बड़े निजी उद्यम के रूप में कृषि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान देती है । हमारा लगभग 50 प्रतिशत कार्यबल इसमें लगा हुआ है। तदनुसार, भारत में आधा कार्यबल अभी भी कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में इस कार्यबल का कम योगदान होने का कारण औसत आधार पर इन्हें उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगे कामगारों से कहीं कम आय प्राप्त होती है और इसीलिए वे सम्पन्न नहीं हैं। देश के समग्र विकास के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास 'पहली एवं जरूरी शर्त' है और इसके लिए हमें अपने किसानों को खुशहाल बनाना होगा, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करनी होगी जिसके प्रति हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं।

7. भारत में छोटे-छोटे खेतों में कृषि की जाती है। कृषि संगणना के अनुसार भारत में संचालनात्मक जोत की कुल संख्या 138.35 मिलियन है और जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर है। कुल जोत में से 85 प्रतिशत जोत 2 हेक्टेयर से कम की सीमान्त और छोटी हैं (कृषि संगणना, भारत सरकार, 2014)। ये छोटे कृषक यद्यपि कुल भूमि के केवल 44 प्रतिशत भाग पर ही खेती करते हैं तथापि राष्ट्र को खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने वाले मुख्य प्रदाता हैं परन्तु प्रौद्योगिकी, निवेशों, क्रेडिट, पूंजी और बाजार सुविधाओं तक इनकी पहुंच बहुत सीमित है। ऐसी प्रौद्योगिकियां एवं नीतियां जो भूमिहीनों, छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करती हों, ग्रामीण परिवारों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए आज की आवश्यकता बनी हुई है।

8. यद्यपि छोटे और सीमान्त किसान बड़े आकार की जोत की तुलना में अधिक उत्पादकता प्राप्त करते हैं परन्तु उनके पास बाजार योग्य सरपल्स कम होता है और वे कम लाभ प्राप्त करते हैं। अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2030 तक छोटे और सीमान्त किसानों की कृषि जोत 91

प्रतिशत से अधिक होंगी। लगातार घट रहे कृषि क्षेत्र के आकार से छोटे फार्मों के टिकाऊपन को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है। वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को इसके बारे में सोचना होगा।

9. भारतीय कृषि के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियों हैं जल संकट, जलवायु परिवर्तन, मृदा निम्नीकरण, आनुवंशिक क्षरण, जैविक एवं अजैविक दबाव, फसलोत्तर हानियां ऊर्जा प्रबंधन, बाजारों में पहुंच एवं बाजार की अनिश्चितताएं और जानकारी की कमी। जीनोमिक्स, क्वालिटी बीज एवं पादप सामग्री, जलवायु परिवर्तन, नैदानिकी एवं टीका, प्रेसीजन कृषि, शुष्क भूमि कृषि, फार्मिंग प्रणाली, संरक्षित कृषि, फार्म यांत्रिकीकरण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जैव संवेदक, स्वास्थ्य खाद्य, चारा और आहार के संबंध में प्रत्याशित एवं कार्यनीतिक अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। नई तकनीकियों को विकसित करने और उन्हें किसानों के बीच में उपयोगी बनाने में अंतर है। हमारे वैज्ञानिकों को इस ओर भी ध्यान देना होगा।

10. देश की युवा पीढ़ी को कृषि के प्रति आकर्षित करने में कृषि शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि अनुसंधान व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नये संस्थान खोले गए हैं जैसे देश के प्रतिष्ठित पूसा संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर आईएआरआई - झारखंड एवं आईएआरआई - असम । राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार का डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU) के रूप में उन्नयन किया गया है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के तहत 6 नए कॉलेज खोले गए हैं और रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। मोतीहारी, बिहार में समेकित कृषि के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया । तदोंग, सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ANGRAU, आन्ध्र प्रदेश और SKLTSHU, तेलंगाना प्रत्येक को रूपये 135 करोड जारी किए गए। कृषि शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए उच्चतर कृषि शिक्षा के कुल बजट में 405 करोड रूपये (2013-14) के मुकाबले में 614.29 करोड रूपये (2017-18) में लगभग 51.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इन सभी प्रयासों से हमारा कृषि तंत्र मजबूत होगा और इसकी पहुंच दूर-दराज तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग तक पहुंचेगी।

11. अनुभवजन्य प्रशिक्षण, कौशल और उद्यमशीलता विकास पर फोकस करते हुए कृषि विषयों में डिग्री कोर्स को संशोधित किया गया है और सभी कृषि विश्वविद्यालयों में पांचवीं डीन समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है। उच्च कृषि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन हेतु नई मार्गदर्शिका तैयार की गई। अभी तक कुल 63 कृषि विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन (Accreditation) प्रदान किया गया है। एक बहुत बड़ी पहल के तहत, रोजगार उन्मुख बनाने के लिए कृषि विज्ञान में डिग्री को प्रोफेशनल घोषित किया गया है। अभी हाल ही में शिक्षा पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। आईसीएआर का यह शिक्षा पोर्टल देश के सभी कृषि

विश्वविद्यालयों से शिक्षा संबंधी जानकारी/घोषणाओं और कार्यक्रमों की सूची एवं ई-लर्निंग पाठ्यक्रम को एकत्रित करके सरलता एवं शीघ्रता से उपलब्ध करायेगा। यह पोर्टल ग्रामीण युवकों को उच्च कृषि शिक्षा प्रदान कराने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इस पोर्टल को माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है और पहली बार किसान समुदाय व छात्रों के हित में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों की सूचनाएं एक मंच से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

12. **पशु चिकित्सा शिक्षा** - स्नातक पशु चिकित्सा शिक्षा के मौजूदा पाठ्यक्रम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूर्व मानकों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित पशु चिकित्सा जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 46 हो गई है। विभिन्न पशु चिकित्सा कॉलेजों में छात्रों की सीटें 60 से 100 तक बढ़ा दी गई हैं। 17 पशु चिकित्सा कॉलेजों में कुल 946 सीटों की संख्या बढ़कर 1334 हो गई है। पशु चिकित्सा स्नातकों की संख्या में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह पशु चिकित्सा कॉलेजों में भी सीटें डेढ़ गुना तक बढ़ गई हैं, पशु चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन में भी वृद्धि हासिल की गई है।

13. अभी हाल ही में आईसीएआर द्वारा उच्चतर कृषि शिक्षा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और इसे मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP)** को प्रारंभ किया गया है जिसमें कुल फण्डिंग 1100 करोड रूपये है। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसमें विश्व बैंक और भारत सरकार की वित्तीय सहायता 50 : 50 होगी। इस मेगा परियोजना से देश के कृषि विश्वविद्यालयों का कायाकल्प होगा और कृषि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से चयनित कृषि विश्वविद्यालयों में उच्च कृषि शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी; छात्रों और संकाय का विकास होगा; प्रशिक्षण परिणामों में रोजगार सृजन और उद्यमशीलता में सुधार आएगा; तथा संस्थान व प्रणाली प्रबंधन की प्रभावशीलता में बढ़ोतरी होगी।

14. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रामीण युवकों का कौशल विकास करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता किया गया है। समझौते के तहत, ग्रामीण युवकों को कृषि, बागवानी, पशु पालन और मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय 690 कृषि विज्ञान केन्द्रों को सहयोग करेगा और युवाओं को जरूरत के अनुसार प्रासंगिक कौशल प्रदान किया जाएगा।

15. ग्रामीण परिवेश में कार्य अनुभव देते हुए छात्रों का कौशल निर्माण करने के प्रयोजन से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 जुलाई, 2015 को **स्टूडेन्ट रेडी** (Student READY) कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसमें जहां वर्ष 2016-17 से पहले 6 माह के प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को 750

रूपये प्रति माह की फेलोशिप दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 3000 रूपये प्रति माह किया गया है। वर्तमान में स्टूडेंट रेडी के तहत ग्रामीण प्रदर्शन कार्यक्रम पूरे एक साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप छात्र नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी प्रदान करने के लिए समर्थ हो सकेंगे। इस दिशा में देशभर में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों में कुल 436 अनुभवजन्य प्रशिक्षण इकाइयां खोली गई हैं। स्टूडेंट रेडी को बुनियादी तौर पर कौशल उन्नयन की दिशा में एक पहल के रूप में विकसित किया गया है जिसके माध्यम से छात्रों को विविध प्रकार से हुनरमंद बनाया जाएगा, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों तथा रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ उनमें अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने की योग्यता का भी विकास हो। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों द्वारा उद्यमशीलता के विकास को गति तथा बल प्राप्त होगा।

16. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा **पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना** के तहत जैविक खेती/प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में पहल की गई। इस प्रयोजन के लिए रूपये 5.35 करोड के बजटीय प्रावधान के साथ 100 केन्द्रों की पहचान की गई है।

17. पहली बार वर्ष 2016-17 के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 3317 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण (skill development training) प्रदान किया गया जिसके लिए एग्रीकल्चरल स्किल्स काउन्सिल ऑफ इंडिया और आरकेवीवाई के साथ सहयोग करके 97 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कुल 188 प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए गए।

18. आज युवाओं को सम्बोधित करते हुए मैं अपना ज्यादा फोकस कृषि क्षेत्र में युवाओं से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों पर केन्द्रित कर रहा हूं । इस कड़ी में टिकाऊ आमदनी और लाभकारी रोजगार के लिए कृषि, सम्बद्ध एवं सेवा सेक्टर में विभिन्न कृषि उद्यमों को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए **आर्या (युवाओं को कृषि में आकृष्ट करना और इससे जोड़े रखना)** परियोजना को लागू किया गया था। यह परियोजना कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 25 राज्यों के 25 जिलों में चलाई जा रही है। कुल 5000 युवाओं के लक्ष्य के साथ, इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 3242 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया । आर्या योजना का उद्देश्य (i) चयनित जिलों में टिकाऊ आय और लाभकारी रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि, संबद्ध सेवा क्षेत्र उद्यमियों की ओर आकर्षित करना और सशक्त बनाना (ii) प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन जैसे संसाधन एवं पूंजीगत सघन क्रियाकलापों को अपनाने हेतु ग्रामीण युवाओं को नेटवर्क समूह स्थापित कराना और (iii) युवाओं के टिकाऊ विकास के लिए विभिन्न योजना कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध अवसरों

के समावेशन के लिए विभिन्न संस्थाओं और हितधारकों के साथ कार्यात्मक सम्पर्क स्थापित करना है।

19. किसानों तक उपयोगी जानकारी और टैक्नोलॉजीज को पहुंचाने के लिए देश के अधिकांश जिलों में स्थित 690 कृषि विज्ञान केन्द्रों की ऑन-लाइन मॉनीटरिंग, प्रबंधन, सूचना एवं सलाह के लिए **कृषि विज्ञान केन्द्र पोर्टल** की शुरूआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से अनेक प्रकार की गतिविधियों यथा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण, मौसम पूर्वानुमान, कृषि सामग्री, बीज उपलब्धता तथा क्षेत्रीय आधारित टैक्नोलॉजीज आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। हमारे किसान भाई सुझाव पाने के लिए किसी भी विशिष्ट केवीके से पूछताछ कर सकते हैं।

20. **स्टार्ट-अप इंडिया** - स्टैंड-अप इंडिया - स्टार्ट-अप इंडिया, भारत सरकार की स्टैंड-अप इंडिया पहल उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है जिससे युवाओं के बीच में नए रोजगार के अवसर बनते हैं और शुरूआती नेटवर्क को स्थापित करने में सहायता मिलती है। यह योजना शुरूआती इकोलॉजी सिस्टम बनाती है जो कि एक सेट-अप के रूप में विकसित होगी। इस योजना के तहत संरक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए 35 नए संस्थानों में इनक्यूबेटर सुविधा प्रदान की गई है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय अनुकूलनता के लिए पोषक तत्वों से भरपूर एवं मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना आज समय की मांग है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि स्टार्ट-अप कार्यक्रम के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। एग्रीनोवेट इंडिया, आईसीएआर का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके द्वारा व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने और इनोवेशन व क्षमता चालित कृषि विकास को उत्प्रेरित करने में उद्यमियों को इंटरफेस की सुविधा प्रदान की जाती है।

21. आज के युवा, भविष्य के इनोवेटर्स, सृजनकर्ता, निर्माता और कर्णधार हैं। परन्तु वे भविष्य में परिवर्तन तभी ला सकते हैं यदि वे कौशल, बेहतर स्वास्थ्य और निर्णय लेने और जीवन में उचित विकल्पों के चयन की क्षमता रखते हों। उचित नीतियों और मानव पूंजी में निवेश के साथ देश की युवाशक्ति को आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए समर्थ बना सकते हैं और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकते हैं। इससे **"वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना"** के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकेगा। हमारे युवा किसान भाइयों व बहनों का इस क्षेत्र में विशेष योगदान होना चाहिए क्योंकि नई पीढ़ी तकनीकी एवं इसके उपयोग की ज्यादा समझ रखती है। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कि सॉफटवेयर, मोबाइल ऐप, पोर्टल आदि का उपयोग करके खेती को आसान और लाभकारी बनाने में आप सभी का अधिक से अधिक योगदान होना चाहिए।

22. आज भारत सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने और कृषि की बेहतरी के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और इस कार्य में सभी जनों का विशेषकर युवा पीढ़ी का सकारात्मक सहयोग अति

आवश्यक है। युवा पीढ़ी में वह क्षमता है जो कि अपने ज्ञान विशेषकर डिजिटल रूप से उपलब्ध नवीनतम टैक्नोलॉजीज, नई अनुसंधान जानकारी, इनोवेशन्स के माध्यम से देश की कृषि को आगे ले जाने में सक्षम हैं। कौशल निर्माण के माध्यम से आज के युवा स्वयं रोजगार देने वाले बनें - ऐसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और मेरी इच्छा है।

इन्हीं शब्दों के साथ में सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे युवा इस देश की प्रगति में विशेषकर कृषि की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

धन्यवाद,

जय-हिन्द